



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 211]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2002/आश्विन 5, 1924

No. 211]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2002/ASVINA 5, 1924

महापतन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितंबर, 2002

सं. टीएमपी/60/2002-केपीटी.—महापतन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए महापतन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार कांडला पतन न्यास द्वारा भण्डारण/किराया प्रभारों की अधिक वसूली के विरुद्ध मै. महेश्वरी हैंडलिंग एजेंसीज पा. लि. द्वारा दिए गए अभ्यावेदन संबंधी मामले को बन्द करता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएमपी/60/2002-केपीटी

मै. महेश्वरी हैंडलिंग एजेंसीज प्रा. लि.

आवेदक

बनाम

कांडला पतन न्यास (केपीटी)

प्रत्यर्थी

आदेश

(सितंबर, 2002 के 20वें दिन पारित किया गया)

यह मामला कांडला पतन न्यास द्वारा भण्डारण/किराया प्रभारों की अधिक वसूली के विरुद्ध मै. महेश्वरी हैंडलिंग एजेंसीज प्रा. लि. द्वारा दिए गए अभ्यावेदन से संबंधित है।

2.1. अब तक, 'दरों के मान बनाने के लिए' इस प्राधिकरण की नियामक मध्यस्थता निष्पत्तिखित मार्गों को व्यक्त कर की जा रही थीः—

- (i) पतन न्यास/निजी टर्मिनल से प्राप्त 'प्रस्ताव' पर विचार।
- (ii) पतन प्रयोक्ता अथवा पतन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि संस्था से प्राप्त 'अभ्यावेदन' पर विचार।
- (iii) अपनी ओर से कार्रवाई करना।

2.2. यह उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण के कार्य विनियम संब्लिहार भी कार्यवाहियों में ज्यादा से ज्यादा पक्षों को भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विचार-विमर्श प्रक्रिया पर जोर देने के अनुसार बनाए गए हैं।

3 उपर्युक्त अभ्यावेदन प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृत किया गया था और निर्धारित विचार-विमर्श पक्रिया का अनुसरण कर अगली कार्यवाही को गई थी।

4 इस मामले पर अंतिम विचार किए जाने से पहले, भारत सरकार (पीत परिवहन मंत्रालय) ने अपने दिनांक 9 सितंबर, 2002 के पत्र सं. पीआर-14019/36/2001-पीजी द्वारा इस प्राधिकरण को महापतन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन 'नीति निर्देश' जारी किया है कि

भविष्य में वैयक्तिक पक्षों द्वारा दिए जाने वाले अभ्यावेदनों पर कार्यवाही न की जाए। इस प्रकार, इस प्राधिकरण को महापतन न्यास अधिनियम के उपबंधों के अधीन वैयक्तिक मामलों में निर्णय देने की शक्ति नहीं है। यह निर्देश इस प्राधिकरण के हस्तर्क के बावजूद आरी किया गया है कि पूर्णकृत धारा 111 के आशय में 'नीति प्रश्न' पर निर्देश जारी करना शामिल है और क्षेत्राधिकार संबंधी किसी विवाद को केवल सभी विधिक मुद्दे के रूप में देखा जाएगा, जब नीति निर्देश के माध्यम से संकल्प की कोई गुंजाहश नहीं होगी।

5. महापतन न्यास अधिनियम की धारा 111 के उपबंधों के अनुसार, यह प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा नीति के प्रश्नों पर एवं गए निर्देशों के बधा हुआ है।

6. उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण उपर्युक्त अभ्यावेदन पर अंतिम विचार करने में असमर्थ है। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त मामला क्षेत्राधिकार के अभाव में, सरकार के निर्देशानुसार, अन्द किया जाता है।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2002/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2002

No.TAMP/60/2002-KPT.— In compliance of a direction issued by the Government of India under Section 111 of the Major Port Trusts Act, the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the case relating to the representation made by M/s. Maheshwari Handling Agencies Pvt. Ltd. against the excess recovery of storage/rental charges by the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/60/2002-KPT

M/s. Maheshwari Handling Agencies Pvt. Ltd.	---	Applicant
	/s	
The Kandla Port Trust	---	Respondent

ORDER

(Passed on this 20th day of September 2002)

This case relates to a representation made by M/s. Maheshwari Handling Agencies Pvt. Ltd. against the excess recovery of storage/rental charges by the Kandla Port Trust.

2.1. So far, the regulatory intervention of this Authority 'to frame Scale of Rates' has been taken to encompass the following routes:

- (i) Consideration of a 'proposal' received from a Port Trust / Private Terminal.
- (ii) Consideration of a 'representation' received from a port user or a representative body of port users.
- (iii) Initiation of action *suo motu*.

2.2. It is noteworthy that the Transaction of Business Regulations of this Authority have also been framed accordingly with an emphasis on a consultative process to promote participation in the proceedings of the greatest number of interested parties.

3. The representation in reference was registered as a tariff case and processed further following the consultative procedure prescribed.

4. Before this case could be taken up for final consideration, the Government of India (in the Ministry of Shipping) vide its communication No. PR-14019/36/2001-PG dated 9 September, 2002 has issued a 'policy direction' to this Authority under Section 111 of the MPT Act to refrain in future from entertaining representations made by individual parties, as this Authority has no power of adjudication in individual cases under the provisions of the MPT Act. This direction has been issued despite this Authority's argument that the scope of Section 111 ibid covers issue of directions on 'question of policy' and any dispute about jurisdiction can only be seen to be a legal issue having no scope for resolution through a policy direction.

5. In terms of the provisions of Section 111 of the MPT Act, this Authority is bound by the directions on questions of policy given by the Central Government.

6. For the reasons given above, this Authority is unable to take up the representation in reference for final consideration. In the result, the case in reference is closed, as directed by the Government, for want of jurisdiction.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT III/IV/143/2002/Exty.]